



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2008/श्रावण 23, 1930

No. 290]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2008/SRAVANA 23, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआती संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2008

निर्णायक समीक्षा

**विषय :** **ताईवान एवं यूएई के मूल से अथवा वहाँ से निर्यातित सन/डस्ट कंट्रोल पॉलिएस्टर फिल्म के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।**

फा. सं. 15/17/2008-डीजीएडी.—यतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1995 में ब्यासशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा कति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 25 जुलाई, 2003 की अधिसूचना सं. 14/53/2002-डीजीएडी द्वारा अन्तिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी तथा दिनांक 26 अगस्त, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 133/2003 द्वारा भारत सरकार द्वारा अन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाना गया था । प्राधिकारी ने दिनांक 30-7-2004 की अंतिम जाँच संबंधी अधिसूचना सं. 14/53/2002-डीजीएडी द्वारा ताईवान एवं यूएई (जिन्हें एतद्वारा संबद्ध देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सन/डस्ट कंट्रोल पॉलिएस्टर फिल्म (जिन्हें एतद्वारा संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जाँच परिणाम जारी किए थे और दिनांक 29-9-2004 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 101/2004 सी.शु. द्वारा भारत सरकार द्वारा निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था ।

## 2. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद ताईवान एवं यूएई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित स्पेशिएलिटी पॉलिएस्टर फिल्म अथवा सन/डस्ट कंट्रोल पॉलिएस्टर फिल्म है । सन/डस्ट कंट्रोल पॉलिएस्टर फिल्म को काँच की खिड़कियों के अंदर के हिस्से पर लगाया जाता है । इसका मुख्य कार्य सौर तथा चमक, परबैंगनी रोशनी तथा चिल्लाती धूप को रोकना है जो सामान्यतः खिड़कियों से अंदर प्रवेश कर जाती है । यह फिल्म काँच को टूटने से भी अधिक बचाती है । सन/डस्ट कंट्रोल पॉलिएस्टर फिल्म को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अन्वय 39 के तहत सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 392069 तथा भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण के तहत 39.20.69.04 के तहत वर्गीकृत किया गया है । तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जाँचों पर बाध्यकारी नहीं है । वर्तमान जाँच एक समीक्षा जाँच है और विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच में परिभाषित उत्पाद ही रहेगा । इसके अलावा मूल जाँच के बाद की अवधि के दौरान उत्पाद में किसी उल्लेखनीय परिवर्तन अथवा बदलाव का कोई दावा नहीं किया गया है । याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है । याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित वस्तुओं के समान वस्तु माना जा रहा है ।

निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित वस्तुओं के समान वस्तु माना जा रहा है।

### 3. समीक्षा हेतु अनुरोध और जाँच की शुरुआत

और यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को यदि अन्यथा पहले ही समाप्त न कर दिया जाए तो उसे लगाए जाने की तारीख से पाँच वर्ष के बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

और यतः, नियमों में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को लगातार जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करना अपेक्षित है और उन्हें प्राप्त हुई सूचना के आधार पर यदि वह संतुष्ट हों कि ऐसे शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी शुल्क को वापस लिए जाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी प्राधिकारी द्वारा उपाय की समाप्ति की तारीख के पूर्व उचित समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत् प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा किया जाना अपेक्षित है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार वर्तमान आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मै. गरवारे पॉलिस्टर्स लि., मुम्बई (जिसे एतद्पश्चात् आवेदक कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा यह दावा किया गया है कि वे देश में संबद्ध वस्तु के 100% उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। चेतावनी पत्र के उत्तर में आवेदक ने एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें ताइवान तथा यूएई के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए समीक्षा जाँच का अनुरोध किया गया है। अपने आवेदन में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। यह दावा किया गया है कि पाटन जारी रहा है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में उसमें और तेजी आने की संभावना है। क्षति के संबंध में यह दावा किया गया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है, तथापि स्थिति अभी भी नाजुक है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति में तेजी आने की संभावना है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को और 5(पाँच) वर्षों तक जारी रखने का अनुरोध किया है।

आवेदन की जाँच के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मानते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन एवं घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पुनरावृत्ति के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए दावे की जाँच करने के लिए यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क के उपबंधों के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क की इस स्तर पर निर्णायक समीक्षा करना उपयुक्त होगा।

### 4. संबंधित देश

वर्तमान जाँच में शामिल देश ताइवान तथा यूएई (जिन्हें एतद्पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) हैं।

### 5. प्रक्रिया :

दिनांक 30.07.2004 की अधिसूचना सं. 14/53/2002-डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम जाँच परिणाम की समीक्षा करने तथा दिनांक 29.09.2004 की अधिसूचना सं. 101/2004-सीमाशुल्क द्वारा अंतिम सीमाशुल्क लगाने के उपरांत प्राधिकारी यह समीक्षा करने के लिए जाँच प्रारम्भ करते हैं कि क्या 1995 में

यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम 1995 के अनुसरण में, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इस समीक्षा में दिनांक 3 मार्च, 2003 को जारी जांच शुरूआत अधिसूचना सं. 14/53/2002-डीजीएडी तथा मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। प्राधिकारी द्वारा ऊपर पैराग्राफ 3 में उल्लिखित आवेदक को उपर्युक्त नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग मानने का प्रस्ताव किया जाता है क्योंकि वह संबद्ध वस्तुओं का 100% उत्पादन करता है।

#### 6. जांच अवधि (पीओआई)

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) दिनांक 1.4.2007 से 31.3.2008 (12 माह) है। तथापि क्षति की जांच की अवधि में जांच अवधि तथा जांच अवधि से तीन वर्ष पहले की अवधि अर्थात् अप्रैल, 2004-मार्च, 2005; अप्रैल, 2005-मार्च, 2006 तथा अप्रैल, 2006-मार्च, 2007 को शामिल किया जाएगा।

#### 7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को उनके भारत स्थित दूतावासों के माध्यम से तथा इस उत्पाद के ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रारूप तथा तरीके से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अवगत कराने हेतु अलग से पत्र भेजे गए हैं :-

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य विभाग  
कमरा नं. 240, उद्योग भवन  
नई दिल्ली-110107

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी निर्धारित प्रारूप तथा तरीके से अपनी सूचना निम्नलिखित अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(5) के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं तथा प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को भी पाटन क्षति तथा नुकसान से संबंधित जांच से सम्बद्ध सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हैं। अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी निर्धारित प्रारूप तथा तरीके से अपनी सूचना निम्नलिखित अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

#### 8. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई संबंधी अनुरोध इस प्रकार भिजवाया जाए, ताकि वह निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख चालीस (40) दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

**9. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना :**

नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे प्राधिकारी को प्रदत्त गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की सय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता हो, तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण :**

नियम 6 के अनुसरण में कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। ऐसे मामले में, जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करता अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हों।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th August, 2008

**(SUNSET REVIEW)**

**Subject: Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed against Import of Sun/Dust Control Polyester Film originating in or exported from Taiwan & UAE.**

**F. No. 15/17/2008-DGAD.**—Whereas the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional Anti-Dumping Duty vide Notification No. 14/53/2002-DGAD dated 25<sup>th</sup> July, 2003 and such provisional duty was imposed by the Government of India vide Customs Notification No.133/2003 dated 26<sup>th</sup> August, 2003. The Authority issued its Final Findings recommending imposition of definitive Anti Dumping Duty on imports of Sun/Dust Control Polyester Film (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Taiwan & UAE (hereinafter referred as subject countries), vide Final Findings Notification No. 14/53/2002-DGAD dated 30.7.2004 and such definitive duty was imposed by the Government of India vide Customs Notification No. 101/2004-Customs Dated 29.9.2004.

**2. Product under consideration & Like Article**

The product under investigation in the present case is Specialty Polyester Film i.e. Sun/Dust Control Polyester Film originating in or exported from Taiwan & UAE. Sun / Dust Control Polyester Film is applied to the inner side of the glass windows. Its main function is to reduce the solar heat glare, ultra violet light and glare that normally would enter through the windows. This film also provides increased shatter resistance. The Sun / Dust Control Polyester Film is classified

under Customs Tariff Heading 39 20 69 under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975, and 39.20.69.04 under Indian Custom Tariff Classification. The Classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations. The present investigation is a review investigation and the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation. Furthermore, there is no claim of significant development or change in the product during the period thereafter. The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from the subject countries. Goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries/territories within the meaning of the Rules.

### 3. Request for Review and Initiation.

And whereas in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 the Anti Dumping Duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

AND WHEREAS the Rules supra require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the Central Government for its withdrawal. Notwithstanding the above provisions, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

In terms of the above provisions, the present application has been filed by M/s. Garware Polyesters Limited, Mumbai (hereinafter referred to as applicant) on behalf of the domestic industry. It has been claimed by the applicant that they represent 100% of the production of subject goods in the Country, as they are the sole producer of the subject goods in India. As a response to the alert letter, the applicant has filed an application requesting review investigations for continuation of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Taiwan & UAE. In their application, the petitioner has claimed that dumping and injury is likely to continue or recur in the event of revocation of anti dumping duty. It has been claimed that dumping has continued and is likely to intensify in the event of revocation of anti dumping duty. With regard to injury, it has been claimed that even though performance of the domestic industry has improved, the situation continues to be fragile and injury to the domestic industry is likely to intensify in the event of revocation of anti dumping duties. The applicant has requested for continuation of the anti-dumping duty imposed on subject goods from subject countries for a further period of 5 (five) years.

On the basis of examination of the application, the Designated Authority considers that the Sunset Review of the Anti-Dumping Duty in force would be appropriate at this stage under the provisions of Section 9A of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995, as amended, to investigate the claim of the applicant about recurrence of dumping and consequential injury to the Domestic Industry in case of cessation of Anti Dumping Duty in place.

3089 GI/08-2

#### **4. Countries Involved:**

The countries involved in the present investigations are Taiwan & UAE (also referred to as subject countries hereinafter).

#### **5. Procedure:**

Having decided to review the Final Findings issued vide Notification No. 14/53/2002-DGAD Dated 30.7.2004 and final duty imposed vide Notification No 101/2004-Customs dated 29.9.2004, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of anti dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury with regard to imports of subject goods originating in or exported from subject countries, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1975, as amended in 1995, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The review covers all aspects of Initiation Notification No. 14/53/2002-DGAD dated 3<sup>rd</sup> March, 2003 and the Final Findings of the original investigations. The Authority proposes to consider applicant as mentioned in paragraph 3 above as domestic industry in accordance with the Rules supra as they represent 100 per cent of the production of the subject goods.

#### **6. Period on Investigation (POI):**

The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1.4.2007 to 31.3.2008 (12 months). The period for injury examination would however include POI and three years prior to the POI, i.e. April 2004-March 2005, April 2005-March 2006 and April 2006-March 2007.

#### **7. Submission for information**

The exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their Embassies in India and importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

Government of India  
Ministry of Commerce & Industry  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties  
Department of Commerce,  
Room No. 240,  
Udyog Bhavan,  
New Delhi-110107

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

#### **8. Time Limit.**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

#### **9. Submission of Information on Non-confidential basis:**

In terms of Rule 7, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reasons thereof is required to be provided.

#### **10. Inspection of public file:**

Any interested party may inspect the public file containing Non-Confidential Version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7). In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority